हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 77 देहरादून, शुक्रवार, 09 सितंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रचार रथ रुद्रपुर में करेगा महिलाओं को जागरूक 4

महाराज ने राज्य में टनल्स और पहाड़ों पर सीमेंटेड सड़कों के निर्माण की पैरवी की

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बेंगलुरु में लिया मंथन में हिस्सा

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बेंगलुरु/देहरादून 9 सितम्बर , प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, मंत्री सतपाल महाराज ने कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ₹मंथन₹ में शामिल होते हुए राज्य में टनल्स और पहाडों पर सीमेंटेड सड़कें , सड़कों के निर्माण की पैरवी की।

कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ₹मंथन₹ शुभारंभ अवसर पर गुरुवार को प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग कर राज्य की ओर प्रतिनिधित्व किया। 8 और 9 सितम्बर 2022 तक चलने वाले इस ₹मंथन₹ शिविर में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बेंगलुरु में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ₹मंथन₹ में सभी राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य में सड़कों के निर्माण में नई तकनीकी के इस्तेमाल और सुरक्षा की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

लोक निर्माण मंत्री महाराज उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा कि पहाड़ों में अधिकांश स्थानों पर गांव सड़कों के ऊपर बसे हैं जिस कारण वायब्रिंग होती है और गांव को खतरा उत्पन्न होता है। उन्होंने जनपद पौड़ी के गुमखाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है इसलिए नेशनल हाईवे निर्माण मानकों में 24 मीटर के स्थान पर 14 मीटर एक्वायर किया जाए जिससे कि गांव बचे रहें। महाराज ने इस अवसर पर कहा कि मंथन में उच्च तकनीक जानकारी दी जा रही है जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के अंदर टनल्स बने ताकि लोग शीघ्रता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके। नई तकनीक को लेकर हमें कार्बन कंटेंट को कम कर करना है। निश्चित रूप से मंथन शिविर में बताई गई नई तकनीक के समावेश से हमारे पहाड़ों में सड़कों का समुचित विकास संभव हो पाएगा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों पर सीमेंटेड सड़कें बने जिससे हिमपात वाले स्थानों में हमारी सड़कें शुद्र ग्रह और यातायात सुचारू रूप से चल सके।

मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मंथन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभव व एक दूसरे के सहयोग पर भी चर्चा की गई जिससे कि मंत्रालय और गडकरी जी की एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है।

UKSSSC महिला आरक्षण पर आंदोलनकारी मंच ने धरना दिया, मांगी सीबीआई जांच

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 9 सितम्बर ,उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर धरना आयोजित किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के 30% आरक्षण को एक्ट बनाकर पुनः लागू करने UKSSSC में हुए सभी भर्ती घपले घोटालों एवं विधानसभा में पिछली दरवाजे से हुई सभी भर्तियों के साथ ही पिछले 22 वर्षो में हुई भर्तियों की CBI से जांच की मांग की।

अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी बेरोजगार संघ के बॉबी पंवार , संयुक्त नागरिक संगठन के ब्रिगेडियर केo जीo बहल के साथ UKSSSC की प्रतियोगिता की छात्राएं व मातृ शक्ति ने मिलकर जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

जगमोहन सिंह नेगी व विक्रम भंडारी कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने हेतु बेरोजगारों का भविष्य बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन के माध्यम से हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में C B I जांच कराने की मांग करते है। रामलाल खंडूड़ी और प्रदीप कुकरेती ने प्रधानमंत्री से मांग की कि जिन प्रतिनिधियों का नाम किसी भी भर्ती से जुड़ा है उनसे तत्काल इस्तीफा मांगकर हटाया जाए एवं भविष्य में ऐसे लोगो के पार्टी टिकट भी काटे जाएं।

द्वारिका बिष्ट और सुलोचना भट्ट ने कहा कि अब प्रदेश को बचाने के लिए फिर राज्य आंदोलनकारियों के साथ ही छात्र शक्ति भी जाग चुकी है। रामनगर से आए प्रभात ध्यानी के साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व विचारक एवं उक्रांद के संस्थापक सदस्य द्वारिका प्रसाद उनियाल जी ने कहा कि पिछले 22 वर्षो से प्रदेश को लूटने का कार्य ही दिखाई दिया। शहीदों ने जो सपने थे वो सब धरे ही रह गए अब पुनः एक क्रांति की अवश्यकता आन पड़ी है।

आज धरने में बेरोजगार युवा, कालेज के छात्र छात्राये , अधिवक्ता , पूर्व सैनिक के साथ ही कई सामाजिक संस्था व संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। केo जीo बहल , द्वारिका प्रसाद उनियाल , जगमोहन सिंह नेगी , रामलाल खंडूड़ी , जगमोहन सिंह नेगी , बाबी पंवार , प्रदीप कुकरेती , जगमोहन सिंह मेंहदीरत्ता , रुकम पोखरियाल , सतेन्द्र भण्डारी , आशीष नोटियाल , जयदीप सकलानी , मोहित डिमरी , हिरदेश शाही , सुरेश कुमार , सुरेश नेगी , महेंद्र रावत (बब्बी) , हरजिंदर सिंह , पूरण सिंह लिंगवाल , लुसुन टोडरिया , गणेश धामी , मोहन सिंह रावत , सुशील चमोली , स्वरूप जोशी , पंचम सिंह बिष्ट , महेश जोशी , केशव उनियाल , मनमोहन सिंह नेगी , गणेश डंगवाल , मनोज ज्याडा ,आदि रहे।

कर्तव्य पथ : बोस की ग्रेनाइट मूर्ति ने बदला 'इंडिया गेट' का इतिहास

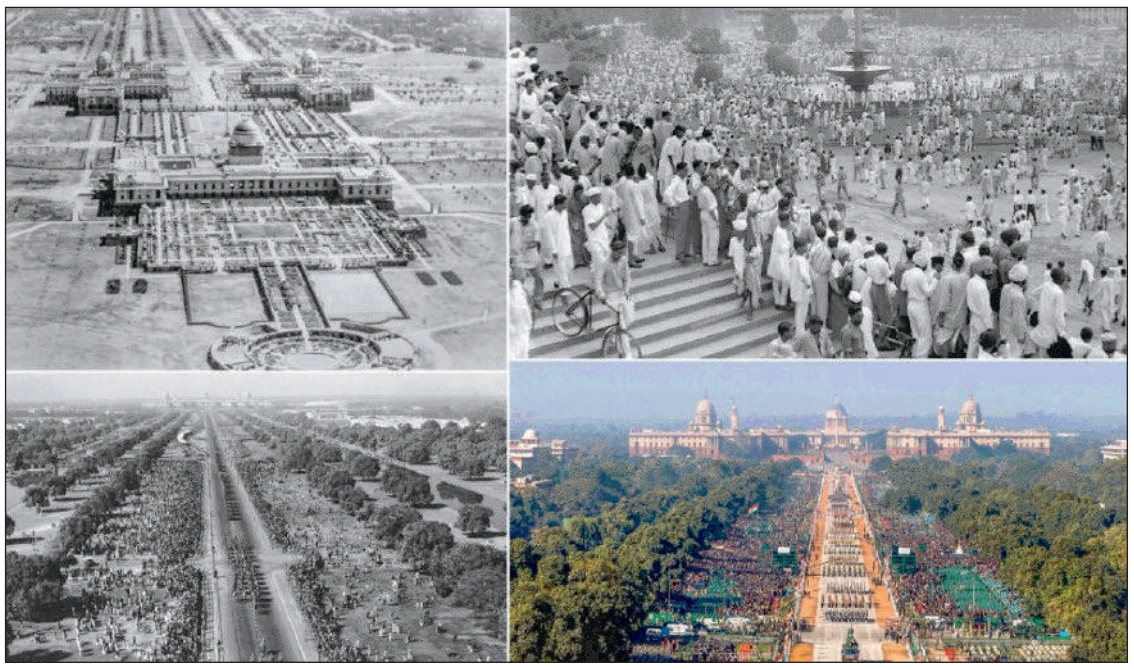

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्र की मोदी सरकार ने उपलब्धियों की श्रृंखला में एक और मील का पत्थर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली का दिल इंडिया गेट इतिहास में एक नए चैप्टर से जुड़ गया है। यहां स्थापित भारत की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा ने साबित कर दिया है कि 'भारत बदल' रहा है। PM मोदी ने 8 सितंबर को इस प्रतिमा का अनावरण किया । इससे पहले नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस (23 जनवरी) को नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। एक ऑफिसियल स्टेटमेंट के अनुसार, नेताजी की भव्य प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक यानी एक ही पत्थर पर पर तराशा गया है। इसे तैयार करने में 26,000 मानव-घंटे(man-hours) लगे। 65 मीट्रिक टन वजनी मूर्ति का निर्माण करने के लिए ग्रेनाइट मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर को तराशा गया।

इस मूर्ति को तैयार करने वाले मूर्तिकारों को ख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज ने लीड किया। मूर्ति का निर्माण मार्डन टूल्स(औजार) की हेल्प से ट्रेडिशनल टेक्निक से किया गया। यानी मूर्ति को तैयार करने में हाथों की कला का ही इस्तेमाल किया गया, मशीन का नहीं। नेताजी की इस विशाल मूर्ति भारत में सबसे ऊंची, रियलिस्टिक मोनोलिथिक ग्रेनाइट (नेचुरल ग्रेनाइट पत्थर), हैंडमेड स्कल्पचर में से एक है। जिस जगह पर ये मूर्ति स्थापित है, वहां PM मोदी ने 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया था। अब जानते हैं इंडिया गेट की कहानी...

नई दिल्ली के केंद्र में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है। यह उन 70,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को शहादत को याद दिलाता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। जब इंडिया गेट बना, तब यहां यूनाइटेड किंग्डम के राजा जार्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसे बाद में बुराड़ी रोड स्थित कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसी चबूतरे(स्तम्भ) पर नेताजी की मूर्ति विराजी है।

फ़ज़ी बेबसाइट पहचानने के 4 हिट फार्मूले जानिए

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 9 सितंबर , नेट आज कल के जीवन का Fack website सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है knowledge of google search और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है गूगल। जी हां आज कल कोई भी चीज सर्च करनी हो, लोग गूगल का सहारा लेते हैं। बड़े तो ठीक है बच्चे तक इसके लिए स्टडी में उपयोग करते हैं। गूगल ने जीवन को जितना आसान बना दिया है उतना ही इसके साथ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि इस गूगल के दौर में कई फर्जी साइड्स भी एक्टिव हो गई हैं। जो आपकी निजी जानकारी चुरा सकती हैं साथ ही इससे कई तरह के फ्रॉड भी बढ़ गए हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि सर्च की गई साइट्स असली हैं या फ्रॉड। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे फर्जी साइट्डस की पहचान कर सकते हैं।

चार तरीके से कर सकते हैं फर्जी वेबसाइट की पहचान –

1 – एसएसएल सर्टिफिकेट SSL certificate

जब आप गूगल पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और आपको SSL certificate डर है कि कहीं ये वेबसाइट फर्जी तो नहीं इसकी पहचान करने का सबसे पहला तरीका है एसएसएल सर्टिफिकेट। आपको इस Google Alert बात पर ध्यान देना है कि आपने जो साइट खोली है वह एसएसएल सर्टिफिटाइड है या नही। दरअसल एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपको अगर किसी

वेबसाइट के आगे लॉक यानी ताले का निशान न दिखाई दे तो ऐसी वेबसाइट को भूलकर भी खोलने की गलती न करें। वो इसलिए क्योंकि ये वेबसाइट सुरक्षित यानि सिक्योर नहीं होती हैं।

2 – पॉप-अप ब्रेक

दूसरे नंबर पर आता है पॉप-अप ब्रेक। Google Alert आप जब भी गूगल पर कोई वेबसाइट खोलें, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं उस पर पॉप-अप ब्रेक तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा किसी वेबसाइट पर हो रहा है। तो समझ जाइए ये साइट फर्जी हैं। ऐसी कंडीशन में आपको इन पर क्लिक करने से बचना चाहिए।

3 – री- डायरेक्ट

तीसरे नंबर पर आता है री डायरेक्ट ऑप्शन। मान लीजिए आपने किसी साइट को खोला है और वह डायरेक्ट न खुलकर किसी और साइट पर ले जा रही है। यानि आपने जो साइट खोली है वह न खुलकर कोई और साइट खुल रही है तो आपको तो इस कंडीशन में आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये वेबसाइट फर्जी हो सकती है।

4 – लुभावने ऑफर्स

चौथे नंबर पर आपको खुद पहचानने की Google Alert जरूरत है वो भी सूझबूझ के साथ। मान लीजिए कोई वेबसाइट आपको बार-बार ऑफर्स देती हैं तो समझ जाइए ये फर्जी हो सकती हैं। क्योंकि ये वास्तविक रूप से आपको आफर नहीं दे रही बल्कि आपका डाटा चुरा रही हैं। जिससे आप ऑन लाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं।

डॉ जसलीन कालरा से जानिए व्यसन उपचार और फिजियोथेरेपी के फायदे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मशहूर फिजीयोथेरपिस्ट डॉ जसलीन कालरा शर्मा का कहना है कि किसी भी लत के लिए फिजियोथेरेपी बहुत प्रभावी उपचार हो सकता है यह शारीरिक कार्यों को बढ़ावा देने और मूड और ऊर्जा को कम करने में मदद करता है। पूर्ण पुनर्वास में व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा, चिकित्सा और अतिरिक्त समग्र दृष्टिकोण जैसे सहायता समूह शामिल हो सकते हैं।

समग्र दृष्टिकोण क्या है ?

समग्र उपचार मॉडल में पूर्ण आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उपचार शामिल हैं जैसे फिजियोथेरेपी ध्यान, योग, मालिश, पोषण चिकित्सा।फिजियोथेरेपी के लाभ

हैप्पी हार्मोन

■ **नशा मुक्ति केन्द्रों में फिजियोथेरेपी होनी चाहिए अनिवार्य - डॉ जसलीन कालरा**

यह व्यक्ति को दिमाग, शरीर और आत्मा को विकसित करने में मदद करता है न केवल दर्द और सुस्ती को कम करने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास और स्वतंत्र भौतिक चिकित्सा रिलीज को बढ़ाता है। शरीर में एंडोमोर्फिन जो वास्तव में दवाओं द्वारा उत्पादित भावनाओं के प्रकारों को उत्तेजित करता है। जिनकी वसूली के हिस्से के रूप में भौतिक चिकित्सा और व्यायाम प्राप्त होता है, लेकिन उनके उचित पुनर्वास को पूरा करने और पुनरावृत्ति से बचने की अधिक संभावना भी होती है।

स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का उत्तराखंड में बनेगा ऑफिस : डॉक्टर आशुतोष सयाना

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में नेत्रदान पखवाड़े का समापन

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में नेत्रदान पखवाड़े 25 अगस्त से 8 सितंबर का समापन हो गया है। इस दौरान रैली और संगोष्ठी का आयोजन राजकीय दून चिकित्सालय में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हेम चंद्र पांडे वाइस चांसलर हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय एवं अतिशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सयाना डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन देहरादून थे।

प्रोफेसर डॉक्टर हेम चंद्र पांडे ने बताया की इस तरीके की जन जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी से अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर किया जाता है और समाज के लिए काफी सफल प्रयास किए जा सकते हैं उन्होंने रिसर्च और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी जीवन में महत्त्व को बड़ी बारीकी से समझाया उन्होंने पौराणिक कथाओं में दधीचि का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी हड्डी तक दान कर दी थी सो उन्होंने अंगदान न नेत्रदान इन सब का महत्त्व प्रामाणिक कथा ओके द्वारा समझाया। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सयाना डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने बताया कि अंगदान का विशेष महत्त्व होता है सबसे सफल प्रत्यारोपण आँखों का ही किया जाता है उन्होंने बताया हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में एसओटीटीओ SOTTO(State organ tissue and transplant organization) स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बनाने के लिए आवेदन भारत सरकार को भेज दिया गया है जिसकी सैद्धांतिक सहमति भी हम लोगों को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गई है आने वाले समय में अंग प्रत्यारोपण के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एक बेहतर भूमिका के रूप में सबके सामने होगा उन्होंने

बताया कि दादी ची नाम से एनजीओ भी अंग प्रत्यारोपण में मदद करने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक सर्जरी और सुपर स्पेशल विभागों में काम कर रहे हैं

प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ रजवी विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग ने बड़े ही विस्तार से अंगदान नेत्रदान की विशिष्टताओं के बारे में बताया की मरने के बाद अगर आप नेत्रदान करते हैं तो दो से तीन लोगों की आँखों में रौशनी को आंख दे सकते हैं सिम्पोजियम में गेस्ट स्पीकर डॉक्टर गौरव लूथरा डायरेक्टर दृष्टि आइ इनस्टिट्यूट ने बड़े ही विस्तार से नेत्रदान के बारे में बताया और और उन्होंने भी इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज आई बैंक जल्द से जल्द स्थापित होना चाहिए उन्होंने अंधा के होने वाले विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनकी रोकथाम और सबसे ज्यादा जो अंधता में हर साल नए मरीज जुड़ते हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए डॉक्टर सुशील ओझा एसोसिएट प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग ने अंधता के बारे में आगे बढ़ते हुए इस बात पर भी विशेष ज़ोर दिया कि हमारे देश में हर साल लोगों के मरने की संख्या 4.7 मिलियन हैं जबकि पूरे अंधेपन को मिलाकर भी ये संख्या छह मिलियन है तो उन्होंने विशेष जोड़ दिया अगर हम अपने देश में अंगदान नेत्रदान को बढ़ावा देते हैं तो न सिर्फ हमारे देश में अंधता को खत्म कर सकते हैं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी आंखो को ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा करके दूसरे देशों के अंता को भी कम करने में एक विशेष योगदान दे सकते हैंडॉक्टर शांति पांडे प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग ने बड़े ही विस्तार से छात्रों के साथ संवाद करते हुए नेत्र दान पखवाड़े में जन जागरूकता के लिए मोटिवेट करा एवं यह भी बताया कि कोविल 19 महामारी के समय नेत्रदान की संख्या भी बहुत कमी आई है जबकि अंधेपन की रोगी बढ़ते ही गए हैं उन्होंने यह भी बताया है कोविंद 19 बीमार व्यक्ति की मौत होती है उसका हम आंखो को दान के लिए सूटेबल नहीं रख सकते और उन्होंने बहुत ही विशेष तरीके से छात्रों को संवाद करते हुए यह भी बताया कि ये नेत्रदान के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं होती मरीज जिसकी यह किसी इंसान की जहाँ भी मृत्यु होती है उसके घर से ही आंखो को आई बैंक के द्वारा लिया जा सकता है और इसके लिए सूचना आप टोल फ्री नंबर 1919 पर दे सकते हैं बच्चों में अंधता का 50% कारण कोर्निया ब्लाइंडनेस होता है अंत में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने अपने सभी स्पीकर एवं श्रोताओं का शुक्रिया अदा करा और बताया कि हम प्रयास करते रहेंगे और जल्द से जल्द आई बैंक दून अस्पताल में स्थापित कर देंगे

खाकी लाई मासूमों के चेहरे पर मुस्कान यही है श्वेता चौबे मैडम की पहचान

ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत चमोली पुलिस ने कराया 2 बालिकाओं का स्कूल में एडमिशन

■ बऑपरेशन मुक्ति" भिक्षा नहीं, शिक्षा दें" "Support to educate a child"

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल से मुक्त कर शिक्षा की ओर अग्रसर करने हेतु प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान को सार्थक बनाने के लिए संवेदनशील और आम जनता के वीच अपनी सहज छवि से खास पहचान बनाने वाली उत्तराखंड पुलिस की सीनियर ऑफिसर पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने एक बार फिर क्षेत्र की जनता का दिल जीत लिया है। उन्होंने जनपद चमोली में लगातार बाल भिक्षावृत्ति एवं मानव तस्करी के प्रति आम जनमानस को अधिक से अधिक जागरुक करने का अभियान चला रखा है। साथ ही ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा सकने के कारण शिक्षा से वंचित हैं। अभियान के तृतीय चरण (School Admission) में ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा गोपेश्वर क्षेत्र में चिन्हित दो बालिकाएँ-

1- कु. शीतल पुत्री- अनिल, निवासी- एन.एच. नया रुड़की रोड बिजली घर के पास जनकपुरी मुजफ्फरनगर उ.प्र.हाल निवासी- नया बस अड्डा जीरो बैंड गोपेश्वर।और

2-तनीषा, पुत्री-अनिल उम्र-06 वर्ष निवासी-उपरोक्त।जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं कराया गया था। पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित कुमार द्वारा दोनों बालिकाओं के माता-पिता की काउन्सलिंग करते हुए उन्हें बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझाया और बच्चों से बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति करवाने पर की जाने वाली कानूनी कार्यवाही की जानकारी दी गयी, जिससे बच्चों के माता-पिता द्वारा विद्यालय में एडमिशन

करवाने के लिए सहमति जताई गई। पुलिस उपाधीक्षक ने परिजनों की सहमति पर दोनों बालिकाओं का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय कुण्ड में कराया गया। दोनों बालिकाओं को स्कूल बैग, शिक्षण सामग्री प्रदान की गई, साथ ही उनके परिजनों से बालिकाओं को लगातार स्कूल भेजने की अपील की गई।वहीं एसपी श्वेता चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी और डीजीपी अशोक कुमार के विजन और मिशन को पहाड़ों में कामयाब बनाने के लिए उनकी टीम जुटी हुई है और जनपद में ऑपरेशन मुक्ति अभियान लगातार जारी है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रचार रथ रुद्रपुर में करेगा महिलाओं को जागरूक

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 9 सितम्बर,, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विकास भवन से मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिसमे गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी जायेगी। उन्होने कहा कि रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण की जानकारी दी जायेगी ताकि वे गर्भ अवस्था में उन्हे दी जाने वाली अर्थिक सहायता दी जा सकें।

उन्होने कहा कि रथ के माध्यम से जनपद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सकें। उन्होने कहा कि योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना है जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय तथा 06 माह पूर्ण होने पर, बच्चे के जन्म के पश्चात टीकारण के समय तीन किस्तो में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि जो महिलाएं गर्भावस्था में कार्य आदि करने में असमर्थ होती है इस दौरान आर्थिक सहायता से अपने व बच्चे का सही ढंग से पोषण कर सकें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस योजना में जनपद की कई महिलाओं द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है जिनके खातों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निरन्तर अर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर-घर जाकर पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं के आवेदन फार्म भरेंगी। योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकरण कराने पर पहली किस्त 1 हजार रूपये, गर्भावस्था के 6 माह बाद दूसरी किस्त 2 हजार रूपये एवं प्रसव के बाद बच्चे का प्रथम चरण का टीकाकरण पूरा होने पर 2 हजार रूपये यानि कुल तीन किस्तों में 5 हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से दिये जाते है। गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर ब्लॉक में सेल्फी प्वाईंट बनाया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर सम्पर्क कर सकते है।

इस अवसर पर प्रधान मंत्री मात्र वंदना के जिला समन्यक किशन महेरा, पोषण अभियान से जिला समन्वयक जया, की टीम मेघा प्रीति अर्पिता अजीत, बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर कविता, नीलम नाथ, लखविंदर , स्वेता दीक्षित,कमला,ज्योति आंगनबाड़ी कार्यकत्रीयां आदि उपस्थित थे।

जल्दी दौलत कमाने के चक्कर में वो बन गया एटीएम क्लोनिंग लुटेरा : एसएसपी अल्मोड़ा ने धर दबोचा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो पकड़ा ही जाता है। अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप राय की टीम ने भी ऐसे ही शातिर लुटेरे को पकड़ा है जो लोगों के बैक खाते में सेंध लगाकर , लाखों रुपये उड़ाने का गुनाह करता था।

खबर ये है कि प्रदीप कुमार राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा ईनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी मिशन के अन्तर्गत अल्मोड़ा पुलिस एवम SOG टीम को एटीएम क्लोनिंग से धोखाधड़ी करने वाला 20 हजार के शातिर ईनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कोतवाली अल्मोड़ा में पंजीकृत अभियोग में गैगस्टर एक्ट बनाम नवनीत शुक्ला आदि 3 के विरुद्ध अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु अथक प्रयास करने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो पाने पर नवनीत शुक्ला के विरुद्ध में मफरूरी में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

मा0न्या0 विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट द्वारा मफरूर अभियुक्त नवनीत शुक्ला के विरुद्ध स्थायी वारन्ट जारी किया गया था। स्थायी वारन्ट की तामील व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर गठित टीम द्वारा दबिश देकर नवनीत शुक्ला को थाना मनकापुर क्षेत्र जनपद गौण्डा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी राय के मुताबिक अभियुक्त गिरोह बनाकर ज्यादा से ज्यादा नोट कमाने के चक्कर में लोगों के साथ तकनीकी रूप से धोखाधड़ी कर स्किमिंग डिवाइस की मदद से एटीएम का डाटा चुराकर इसके द्वारा एटीएम का क्लोन तैयार कर लोगों के खाते से अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता था।नवनीत शुक्ला बीएड/एमएड शिक्षा प्राप्त है, नौकरी ना मिलने पर शीघ्र धन कमाने की लालसा में एटीएम क्लोनिंग कर ठगी का काम कर रहा था, वर्तमान में ठेकेदारी बिल्डिंग बनाने का कार्य करता है । पुलिस की गिरफ्त में आ गया ।

उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2022 के ड्राफ्ट पर आप भी दीजिये अपने सुझाव : नितिन उपाध्याय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी नितिन उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2022 का ड्राफ्ट लोगों के सुझाव हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 से प्रकाशित किया गया है। प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 पर यदि अभी भी कोई व्यक्ति सुझाव देने के इच्छुक हो तो 15 सितम्बर, 2022 तक विभागीय Email-ufdc2015@gmail.com पर भेज सकते हैं। 15 सितम्बर, 2022 तक प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए फिल्म नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं लोक संस्कृति को विश्व पटल पर लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में देश-विदेश से फिल्म निर्माता/निदेशक को शूटिंग हेतु आकर्षित करने, फिल्म सेक्टर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के साधन सृजित करने, क्षेत्रीय फिल्म जगत को मजबूती प्रदान करने एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, फिल्मों को अनुदान, फिल्म पुरस्कार-सम्मान, उत्तराखण्ड की बोलियों में बनने वाली फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा ''उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2022'' का ड्राफ्ट तैयार कर लोगों के सुझाव प्राप्त करने हेतु 20 जुलाई, 2022 का विभागीय वैबसाईट लिंकः http://www.uttarainformation.gov.in/images/download/filmpolicydraft2022.pdf पर अपलोड किया गया है।

आयुक्त सुशील कुमार ने टास्क फोर्स बनाकर अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही के दिए निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 9 सितम्बर , मा0 उच्च न्यायालय द्वारा देहरादून में याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु दाखिल रिट के क्रम में पारित आदेशों के परिपालन एवं सिंचाई विभाग की नहर व अन्य नदी नालों एवं भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली।

उन्होने चिन्हित अतिक्रमण की शेष मामलों पर तेजी लाते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिये। जबकि नहर व अन्य नदी, नालों एवं भूमि पर अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए संयुक्त टीम/टास्क फोर्स टीम बनाकर स्थायी एवं अस्थायी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश।

बैठक में आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने राजपुर कैनाल पर चिन्हित किए गए अतिक्रमण के सापेक्ष हटाए गए अतिक्रमण एवं लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राजपुर कैनाल क्षेत्र में 31 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 17 हटाये गए है तथा 14 पीपी एक्ट में लंबित है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीपी एक्ट में लंबित प्रकरणों की पैरवी करने तथा उन्हें निस्तारित कराने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही दिलाराम से ऊपर की ओर जहां नहर को ढक्कर अतिक्रमण किया गया है ऐसे स्थानों पर चिन्हिकरण हेतु जिलाधिकारी की ओर से संयुक्त टीम/टास्कफोर्स बनाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी प्रशासन को दिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि संयुक्त टीम/टास्कफोर्स में नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सिंचाई विभाग के अभियन्ता, नगर निगम के सहायक अभियन्ता भूमि एवं संबंधित अधिकारी को शामिल किया जाए, जो कि स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण को चिन्हित करेंगे। साथ ही अतिक्रमित भूमि पर पास हुए मानचित्र का भी परीक्षण करेंगे। उन्होंने मालदेवता क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर भी कार्यवाही करने तथा जिन कार्मिकों की इसमें संलिप्तता है उन पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गढी डाकरा में चिन्हित अतिक्रमण हटाने के लिए कैन्टोमेन्ट बोर्ड के सीओ से बात कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा जिन प्रकरणों पर मा0 न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है पर प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए।

अँधेरी रातों में अवैध खनन पर डीएम युगल किशोर की ताबडतोड छापेमारी में बडी कामयाबी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 9 सितम्बर , जिलाधिकारी के निर्देशन में देर रात हुई 13 जगहों पर छापेमारी में 22 वाहन सीज करने के साथ ही 1318500 रूपये की धनराशि आरोपित की गई। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देशों के क्रम मे 7 सितम्बर को देर रात्रि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन, ओवर लोडिंग आदि के रोकथाम हेतु उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। काशीपुर में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व मे 02 जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई जिसमें 15 वाहनों की चेकिंग करते हुए 04 वाहनों को सीज किया गया तथा 3 वाहनों एमवी एक्ट में चालान करने के साथ ही 2 लाख 98 हजार रूपये की धनराशि आरोपित की गई। बाजपुर में उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी के नेतृत्व में 03 छापेमारी की कार्यवाही की गई जिसमें 21 वाहनों की चेकिंग करते हुए तीन वाहनो पर 2 लाख 21 हजार 500 रूपये की धनराशि आरोपित की गई। रूद्रपुर में उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह के नेतृत्व में में 01 स्थान पर रूककर छापेमारी की कार्यवाही की गई, जिसमें 18 वाहनों की चेकिंग करते हुए 07 वाहनों को सीज करने के साथ ही 2 लाख 49 हजार रूपये की धनराशि आरोपित की गई।

किच्छा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में 01 छापेमारी की कार्यवाही की गई, जिसमें 45 वाहनों की चेकिंग करते हुए 11 वाहनों को सीज करने के साथ ही 5 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि आरोपित की गई। सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के नेतृत्व में दो स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए 25 वाहनों की चैकिंग की गई। खटीमा में उप जिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट के नेतृत्व में 2 जगहों पर छापेमारी करते हुए 07 वाहनों की चैकिंग की गई। जसपुर में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा के नेतृत्व में 02 जगहों पर छापेमारी करते हुए 10 वाहनो की चैकिंग की गई।

ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे दो करोड़, नई खेल नीति के तहत पुरस्कार राशि के लिए शासनादेश जारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 8 सितंबर। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने व प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों पर अब धनवर्षा होगी। प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति के तहत पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों को पुरस्कार राशि देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। पूर्व में दी जाने वाली पुरस्कार राशि में नई खेल नीति में 30 से 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नई खेल नीति में पुरस्कार राशि समेत अन्य कई ऐसे प्रविधान किए हैं, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रदेश के भीतर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को पुरस्कार राशि प्रदान करने के लिए नई खेल नीति के तहत शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें प्रतियोगिता में पदक विजेता व प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों की धनराशि बढ़ाई गई है। प्रशिक्षकों को खिलाड़ियों को मिलने वाली धनराशि से आधी धनराशि देने का प्रविधान किया गया है।

शंकरपुरी गांव में 40 मरीजों की रैपिड जांच में 22 मिले डेंगू पाजीटिव, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुड़की, 8 सितंबर। शंकरपुरी गांव में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को एक बार फिर स्वास्थ्य शिविर लगाकर 40 बुखार पीड़ितों के रक्त के सैंपल लिए। इनमें 22 मरीज रैपिड जांच में डेंगू पाजीटिव मिले।

इसके बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है, जिसमें 68 डेंगू पीड़ित सिर्फ शंकरपुरी के हैं। वहीं एक महिला की मौत भी हो चुकी है। हालांकि ग्रामीण विभागीय आंकड़ों को गलत बता रहे हैं और गांव में अधिक मरीज होने की बात कह रहे हैं। उधर, गुरुवार को एक डेंगू पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने पर उसे मेला अस्पताल हरिद्वार में भर्ती कराया गया।

टीम ने गांव में घूमकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया। इसके अलावा ग्रामीणों को डेंगू के लार्वा को लेकर जागरूक करने के साथ ही पर्चे भी बांटे।

एमपैक्स बनाकर समितियों को 84% प्रॉफिट में ला दिया : डॉ धन सिंह रावत

धनदा ने सहकारिता मंत्रियों के सम्मलेन में अमित शाह के सामने गिनाई उपलब्धियां

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नई दिल्ली 9 सितम्बर , देश भर के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में देश की राजधानी में हुआ। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत इस सम्मेलन में शामिल हुए । अपने संबोधन में डॉ रावत ने कहा कि, जब उत्तराखंड में पैक्स समितियां थी, तब वह 22 पर्सेंट प्रॉफिट में थी, हमने उन समितियों को एमपैक्स बनाकर उन समितियों को बाजार देकर 84% प्रॉफिट में ला दिया है।

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ₹ 3400 करोड़ की एनसीडीसी परियोजना, उत्तराखंड सहकारिता विभाग को जो दी है उससे हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर ली है। उन्होंने कहा परियोजना की मदद से बनाया जा रहा बद्री घी हम लोग अमेजन के माध्यम से 2500 रुपए किलो बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 15000 बकरी पालकों को 10-10 बकरियां फ्री दी जा रही है और हिमालयी गोट विलेज बनाए जा रहे हैं।

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि हम मिनट मिशन योजना को कोपरेटिव सोसायटी के माध्यम से सफलम ढंग से चला रहे हैं। पहाड़ी गोदा, झंगोरा ,मंडवा, लाल चावल, राजमा एमपैक्स के जरिये पहाड़ी किसानों को उचित मूल्य देकर खरीद रहे हैं फिर देश विदेश में ऑन लाइन माध्यम से बेच रहे हैं। इसमें बहुत डिमांड आ रही है।

डॉ रावत ने कहा कि गंगोत्री से गंगा जल देश विदेश में श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सहकारिता विभाग भेज रहा है। उत्तराखंड में मशरूम की खेती, सेब के नए बागान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दून सिल्क को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक करोड़ रुपये के प्रॉफिट में उत्तराखंड कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन आ गया है। राज्य में कोपरेटिव ने शिल्क का नया बाजार दिया है।

सहकारिता सम्मेलन में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने जो 7 सुझाव दिए जो इस प्रकार से हैं -

1.सहकारी संस्थाओं में परिवारवाद खत्म करने को नीति बनाई जाए।

2.पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के साथ बैंकिंग का यूनिफार्म कोर बैंकिंग सलूशन लाया जाए

3.पैक्स और FPO एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करे

4.मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋणों में कोलेक्टरल सिक्योरटी की सीमा कम की जाए

5 .सहकारिता विश्वविद्यालय का कैम्पस प्रत्येक राज्य में खोला जाए

6.हिमालयी राज्यो को 90%और 10%के अनुपात में केंद्र की योजनाओं में सहायता उपलब्ध कराई जाए

7 - सहकारी संस्थाओं मेंपारदर्शी भर्ती की व्यवस्था किये जाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए

नई दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबन्धक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय, अपर निबन्धक आनंद एडी शुक्ल शामिल हुए।

आजादी के अमृत काल में समान नागरिक संहिता एक बडी इबारत होगी : सीएम

सीएम ने प्रदेशवासियों से सुझाव देने की अपील की

मो0 सलीम सैफ़ी की विशेष रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

- प्रदेश में बनाई जा रही समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए भी होगी अनुकरणीयः सीएम
- समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यगणो के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने समिति के अब तक के कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्धजनो के साथ आम जन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिये हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशो के लिये भी अनुकरणीय होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में उत्तराखण्ड की जनता का सकारात्मक रेस्पोंस है।अच्छी भावना के साथ किये गये कार्य सफल होते हैं। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (से.नि.) रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध मे सुझाव प्राप्त करने के लिये पोर्टल/वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया गया है। इस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्तूबर तक भेज सकते हैं। समिति हर सुझाव पर पूरी गम्भीरता से विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आज़ादी के अमृत काल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपने सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए। प्रदेश के सभी नागरिकों और हितधारकों को एसएमएस और व्हाट्सएप पर पोर्टल के लिंक के साथ अपील भेजी जा रही है। जिसके माध्यम से वे अपने सुझाव एक माह के भीतर दे सकते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखण्ड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों - विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव व संरक्षता विषयक सहित - पर मसौदा कानून तैयार करने या मौजूदा कानून में संशोधन करने तथा समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्बंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की अनेक बैठकें हो चुकी हैं जिनमे व्यापक विचार विमर्श किया गया है। अब https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया गया है। इस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्तूबर तक भेज सकते हैं।इस दौरान समिति के सदस्य जस्टिस (से.नि.) प्रमोद कोहली, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह (से.नि. आईएएस), प्रो सुरेखा डंगवाल, सदस्य सचिव एवं अपर स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बेरोजगारों के लिए खोले दरवाजे, निकली 955 पदों पर भर्ती

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर आप शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपके लिए ख़ुशख़बरी है। आपको बता दे उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बेरोजगारों के लिए 955 पदों पर भर्ती। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सभी आउटसोर्स भर्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी. इतना ही नहीं शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के मुताबिक जल्द ही एक हजार शिक्षकों को 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरू स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान भेजा जाएगा. इसके अलावा प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास के लिए आईआईएम काशीपुर में एक सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा है. वहीं बीआरपी/सीआरपी की नियुक्ति में विभागीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक स्थायी योजना बनाई गई है और आवेदन करने वाले उम्मीदवार सभी के अंक और योग्यता देख सकेंगे।

संपादकीय

भारत-बांग्लादेश संबंध

कुशियारा नदी समझौते के साथ भारत और बांग्लादेश संबंधों को नयी गति मिली है. इससे पहले 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ था. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे की यह भी उल्लेखनीय उपलब्धि है कि व्यापक व्यापार समझौते और आतंक व अतिवाद पर सहयोग को लेकर भी चर्चा शुरू हो गयी है. अतिथि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहने से दोनों देश विभिन्न मसलों का समाधान निकाल सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने भी घोषणा की है कि जल्दी ही व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए बातचीत शुरू होगी. उल्लेखनीय है कि 2021-22 में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना था. भारत से निर्यात का वह चौथा सबसे बड़ा गंतव्य भी है. भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है तथा एशिया में उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है. निश्चित रूप से हाल के समय में व्यापारिक सहयोग का बढ़ना उत्साहवर्द्धक है, लेकिन इसके विस्तार की अभी बहुत संभावनाएं हैं. दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है. ऐसे में व्यापक व्यापार व आर्थिक सहयोग के लिए ठोस समझौते की दरकार है. इस संबंध में अनौपचारिक रूप से वार्ता 2018 से ही चल रही है, पर कोरोना महामारी के कारण इसमें अवरोध आ गया था. भले ही इन वर्षों में समझौते की ठोस रूप-रेखा तैयार नहीं हो सकी है, लेकिन हालिया वर्षों में व्यापारिक संबंधों के सशक्त होने के पीछे इन वार्ताओं का बड़ा योगदान है. उल्लेखनीय है कि जून, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के समय एक पंचवर्षीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था, जिसकी अवधि स्वतः बढ़ती रहती है. दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के तहत कई भारतीय उत्पादों पर बांग्लादेश में विशेष शुल्क दरें लागू होती हैं. वर्ष 2011 में भारत ने भी बांग्लादेश के उत्पादों पर शुल्क हटा दिया था. बीते एक दशक में हुए अनेक संबंध यह इंगित करते हैं कि दोनों पड़ोसी देश एक-दूसरे के लिए बहुत महत्व रखते हैं तथा एक-दूसरे को मान भी देते हैं. बिमस्टेक समूह की पहलों के तहत भी दोनों देश अनेक बहुपक्षीय प्रयासों में भागीदार हैं. भारतीय वाणिज्य व व्यापार को पूर्वी एशिया में विस्तार देने के प्रयासों में बांग्लादेश हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी है. वर्ष 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी. तब से अब तक दोनों देशों के बीच किसी तरह की तनातनी नहीं रही है. आशा है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में परस्पर संबंध उत्तरोत्तर सशक्त होंगे.

देहरादून स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत इलैक्ट्रिक बसों का आई0एस0बी0टी0 से सहस्त्रधारा रोड पर हुआ शुभारम्भ

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे देश में विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटी के रूप में आधुनिकीकरण एवं विकास कार्यों हेतु कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रगति में हैं। जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश में देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु तृतीय चरण में चयनित किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत कुल 27 परियोजनाएं प्रस्तावित थी जिसमें से 05 परियोजनाओं को पहले ही पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जा चुका है। अन्य परियोजनाओं का कार्य वर्तमान समय में प्रगति पर है। कैबिनेट मंत्री वित्त एव शहरी विकास प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मेयर देहरादून सुनील उनियाल रगामार एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 05 इलैक्ट्रिक बसों का आई0एस0बी0टी0 से सहस्त्रधारा रूट तथा 04 नव निर्मित स्मार्ट टॉयलेटः 1-परेड ग्राउण्ड (पन्त रोड) 2- पुरानी तहसील परिसर 3- सब्जी मण्डी परिसर 4- आई0एस0बी0टी0 परिसर का संचालन का शुभारम्भ कर देहरादून की जनता को समर्पित किया गया।

इलैक्ट्रिक बस

देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं इबै ट्रॉस कम्पनी के मध्य अनुबन्ध के तहत आज देहरादून स्मार्ट सिटी के द्वारा 05 और इलैक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार देहरादून नगर में वर्तमान में कुल 20 ई-बसों का बेडा तैयार हो गया है। आई0एस0बी0टी0 से सहस्त्रधारा रूट पर यह बसें चलाई जायेंगी जिसमें एक ओर जाने में लगभग कुल 21 किमी0 हेतु 37 बस स्टॉपेज (विराम स्थल) निर्धारित किये गये है जो निम्नवत हैः-

क्र0 सं0 बस स्टॉप के नाम क्र0 सं0 बस स्टॉप के नाम -1. आई0एस0बी0टी0 2. शिमला बाई पास 3. माजरा 4. आई0टी0आई0 निरंजनपुर 5. सब्जी मण्डी चौक 6. पटेल नगर पुलिस चौकी 7. लाल पुल 8. पी0एन0बी0 पटेल नगर 9. माता वाला बाग 10. सहारनुपर चौक 11. रेलवे स्टेशन 12. प्रिंस चौक 1 3 . साइबर पुलिस स्टेशन 14. तहसील चौक 15. दर्शनलाल चौक 16. घण्टाघर 17. गांधी पार्क 18. सैन्ट जोसेफ एकेडेमी 19. सचिवालय 20. बहेल 21. दिलाराम चौक 22 मधुबन होटल 23. अजन्ता चौक 24. कन्डोली 25. एन0आई0वी0एच0 बैक गेट 26. बा ला सुन्दरी मन्दिर 27. दुर्गा विहार 28. हैप्पी एन्कलेव 29. पॉलीकिड स्कूल 30. राजुपर रोड एन्क्लेव 31. आई0टी0 पार्क 32. गुजरादा मानसिंह रोड 33. तिब्बतियन कालोनी 34. किरसाली ग्राम 35. कुलहान ग्राम 36. पैसेफिक ग्लोफ 37. सहस्त्रधारा

चौकआई0एस0बी0टी0 से सहस्त्रधारा रूट तक संचालित इन ई-बसों की सुविधा अन्य साधनों की अपेक्षा विशेष तौर पर सस्ती एवं सुगम यात्रा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी।इन ई-बसों में सफर हेतु न्यूनतम किराया मात्र रू0 10 निर्धारित किया गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत चलने वाली इलेक्ट्रिक बस परियोजना में कुल 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा।देहरादून नगर में आज से 05 ई बसों के संचालन के शुभारम्भ के साथ कुल 20

इलैक्ट्रिक बसों के संचालन का मुख्य उद्देश्य वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त, बेहतर सुविधा युक्त पब्लिक ट्रासपोर्ट को बढावा देना है।वर्तमान में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आई0एस0बी0टी0 से राजपुर रोड एवं आई0एस0बी0टी0 से सेलाकुई व रायपुर तथा एयरपोर्ट रूट में संचालित 15 बसों के माध्यम से अब तक कुल 980474 यात्रियों को सुविधायुक्त यात्रा प्रदान कर मात्र 02 वर्ष के अन्तर्गत देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को रू0 1.91 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ है। ई बस में प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 लोग सफर कर रहे हैं।

जी0पी0एस0 सिस्टम एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा सहित सभी मानकों एवं सुविधा युक्त इस ई-बस में व्हीलचेयर खडी करने के लिए स्थान के साथ ही हाईड्रोलिक रैम्प की भी सुविधा देकर दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बस में चालक सहित कुल 26 सीटें उपलब्ध है। यह बस एक बार में पूर्ण चार्ज होने पर लगभग 150 से 170 कि0मी0 तक का सफर तय कर सकती है।

यू0टी0सी0 डिपो ट्रांसपोर्ट नगर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है।

स्मार्ट टॉयलेट

स्मार्ट सिटी परियोजना, कुल लागत रू0 1.09 करोड, के अन्तर्गत देहरादून शहर में अब तक कुल 07 स्मार्ट टायलेट का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जिसमें 03 टॉयलेटस पूर्व में ही जन सुविधा हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं एवं आज 04 स्मार्ट टायलेटस, कुल निर्माण लागत रू0 73.63 लाख, का लोकार्पण किया जा रहा है। इन स्मार्ट टॉयलेटस में महिला, पुरूष तथा दिव्यांगों के लिए पृथक रूप से व्यवस्थायें प्रदान की गई हैं। समस्त स्मार्ट टायलेट पूर्ण रूप से जी0पी0आर0एस0 युक्त हैं एवं इनमें स्वचालित सफाई व्यवस्था जैसे-स्वचालित फ्लशिंग, कॉन्टेक्टलैस हैंड वाशिंग, हैंड ड्रायर, सोप डिस्पेंसर आदि के साथ ही महिलाओं के लिए विशेष रूप से सैनेटरी वेन्डिंग एवं डिस्पोजेबल मशीन लगाई गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टायलेट के प्रयोग मे मुफ्त यूरेनल एवं टायलेट हेतु सुविधा शुल्क मात्र 05 रू0 रखा गया है जिसका भुगतान डिजिटल अथवा कैश के माध्यम से किया जा सकता है।टॉयलेट में WC हेतु सुविधा शुल्क मात्र 05 रू0 रखा गया है जिसका भुगतान डिजिटल अथवा कैश के माध्यम से किया जा सकता है।

कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले 50% से 90% लोगों में हो सकता है कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कोविड-19 महामारी की बदौलत अब हम पहले की तुलना में डिजिटल स्क्रीन के सामने अधिक समय बिता रहे हैं। आज की दौर में सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता चाहे काम के लिए हो, मनोरंजन के लिए हो या महामारी के बीच दोस्तों और साथियों के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी आंखों पर भारी पड़ रही है। संक्रामक वायरल बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) और ऑनलाइन कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस नए सामान्य ने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम (सीवीएस) या डिजिटल आई स्ट्रेन की घटनाओं में वृद्धि की है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है।

कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षणों के लिए देखें

कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम एक विशिष्ट समस्या नहीं है। इसमें एक समय में घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरने के परिणामस्वरूप होने वाली आंखों की समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। यह अनुमान लगाया गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले 50% से 90% लोगों में कम से कम कुछ सीवीएस लक्षण होते हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नियमित कंप्यूटर के उपयोग से आंखों को कोई दीर्घकालिक नुकसान होता है, इससे धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि, सूखी और लाल आंखें, आंखों में जलन, सिरदर्द, गर्दन या पीठ दर्द, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और अन्य जैसे लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम आपके कार्य प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है।

जब आप स्क्रीन को बहुत देर तक देखते हैं, तो पलक झपकने की दर कम हो जाती है और इससे आंखें सूख जाती हैं और काम करते समय समय-समय पर आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। साथ ही, जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी आंखों को हर समय ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और इसके लिए आपकी आंखों की मांसपेशियों से बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, स्क्रीन कंट्रास्ट, झिलमिलाहट और चकाचौंध को जोड़ती है। ये सब आपकी आंखों पर वास्तविक दबाव डाल सकते हैं और असुविधा पैदा कर सकते हैं।

कंप्यूटर विजन सिंड्रोम विकसित होने से बचने के लिए टिप्स

सीवीएस विकसित होने से बचने के लिए, स्क्रीन के समय की अवधि को कम करना चाहिए, स्क्रीन के रिज़ॉल्यूशन को कम करना चाहिए और यहां तक कि आई ड्रॉप जैसे

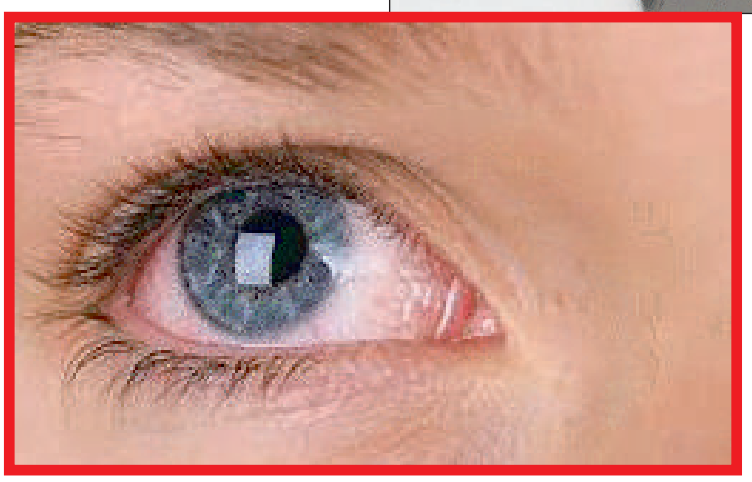

सप्लीमेंट्स का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए, सामान्य स्क्रीन टाइम एक बार में अधिकतम 30-35 मिनट होना चाहिए। बच्चों को सीवीएस विकसित करने से रोकने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले लोगो को 30-35 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए और नहीं तो 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिये जिसमे उन्हें अपनी आँखों को ठंडे पानी से साफ़ कर लेना चहिए।

विशेषज्ञों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले पेशेवरों के लिए सीवीएस परिणामों से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है।

1. पेशेवरों को हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेने और 20 फीट दूर कुछ देखने की सलाह देते हैं। इससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा और साथ ही आंखों, गर्दन और पीठ में रक्त संचार बढ़ेगा।2. कमरे की रोशनी, शरीर की स्थिति, कंप्यूटर स्क्रीन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए।3. पैनलिस्टों ने यह भी सुझाव दिया कि माता-पिता को अपने बच्चों को जन्म के एक साल बाद से ही आंखों की जांच के लिए ले जाना चाहिए।

भारत में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है, जो पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। इसलिए, आंखों की स्थिति के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए ।

डीएम सोनिका और एसएसपी ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने के लिए उतरे फील्ड में

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 8 सितम्बर , जिलाधिकारी सोनिका एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुँवर ने संयुक्त रूप से प्रिंस चैक, सहारनपुर चैक, पटेलनगर चैक, आईएसबीटी से कारगी चैक हरिद्वार बाईपास रोड़, रिस्पना तक स्थलीय निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यातायात में बाधक बन रहे पोल, अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग तथा सड़कों पर निर्माण सामग्री आदि को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि यातायात व्यवस्था सुगम रहे। उन्होंने आईएसबीटी से कारगी चैक हरिद्वार बाईपास रोड़ पर सड़क चैड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़क निर्माण सामग्री को सुव्यवस्थित करने के साथ ही निर्माण कार्य के पश्चात सड़क को यथाशीघ्र पूर्व अवस्था में लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी लि0 के कार्यों का भी निरीक्षण किया।यातायात पुलिस को सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे दुकान, रेड़ी, ठेली, फड़, वालों को भी अपने सामान को सुव्यवस्थित रखते हुए सड़क/फुटपाथ से हटाते हुए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, पुलिस अधीक्षक नगर सरिता डोभाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय, अधि0 अभि0 लोनिवि डीसी नौटियाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अगले 24 घंटे चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

देहरादून, 8 सितंबर। उत्तराखंड में मौसम फिर करवट बदलेगा। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए नदियों, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा